have been advised to pay focused attention on the high value suit filed accounts. In addition to the above, the following measures are being taken by the Government/Reserve Bank of India (RBI) to ensure that banks do not incur losses.

(1) RBI holds annual discussions on various performance parameters with the Top Executives of Nationalsed Banks to review their performances against various parameters and vis-a-vis the commitments for performances made earlier. Banks also commit to attain higher levels of business and performance to improve profitability, recovery of NPAs, tone up housekeeping and staff productivity.

(2) With the introuduction of prudential norms, banks have evolved their loan recovery policies and have set up loan recovery cells to effect speedy recoveries of NPAs.

(3) Banks have also been asked to strengthen their credit appraisal and supervision machinery to improve the quality of assets and to reduce addition of fresh NPAs.

(4) Debt Recovery Tribunals (DRTs) have been set up to help banks in the recovery of dues.

(5) Loss making banks are advised to refreain from incurring fresh capital expenditure, other than for computerisation/automation and undertaking branch expansion and fresh recruitment of staff and reduce all operating expenses through rationalisation of their organisational structure.

रामगढ़ पर्वत में हाई पावर टी०वी० ट्रांसमीटर परियोजना के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता

678. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैसलमेर स्थित रामगढ़ पर्वत में हाई पावर टी०वी० ट्रांसमीटर परियोजना के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए स्टाफ की मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या 1993 में उक्त ट्रांसमीटर परियोजना के पूरी हो जाने पर भी, 5 वर्ष तक स्टाफ की मंजूरी न देने के लिए उत्तरदायी कर्मियों के विरूद्ध जांच प्रस्तावित है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना से प्रसारण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) आंशिक पूरक स्टाफ की स्वीकृति मिल गयी है।

(ख) स्टाफ की स्वीकृति में विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हुआ था तथा किसी भी कार्मिक को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता।

(ग) प्रसार भारती द्वारा स्वीकृत पदों पर स्टाफ की तैनाती करते ही ट्रांसमीटर से कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

बिहार में आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव

679. **श्री जनार्दन यादव:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने हाल ही में आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में विद्यमान दूरदर्शन ट्रांसमीटर एवं आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या सम्पूर्ण आबादी एवं क्षेत्र में अपने कार्यक्रम को पहुंचाने की दृष्टि से अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार के बांका स्थान में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। बिहार में मौजूदा रेडियो केन्द्र राज्य के 99% क्षेत्र तथा जनसंख्या को कवरेज प्रदान करता है। जब कि बिहार के लगभग 94.4% क्षेत्र तथा 94.2% जनसंख्या को स्थलीय रूप से टी०वी० सेवा उपलब्ध है। तथापि, पूरे राज्य को उपग्रह प्रणाली के माध्यम से टी०वी० सेवा उपलब्ध है।

(ग) बांका में फिलहाल, टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।